7 OCT 6 2026.qxd 06-10-2026 19:10 Page 1

प्रासंगिक हस्तक्षेप

सर्वोच्च न्यायालयके प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकान्तकी अध्यक्षता वाली पीठने सोमवारको विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान मतदाता सूचीमें नाम शामिल करनेके लिए उपयोगमें आने वाले फार्म-६ में किसी भी बदलावको मंजूरी नहीं दी है। भारत निर्वाचन आयोगके दावेके बाद न्यायमूर्ति सूर्यकान्तका यह कहना भी महत्वपूर्ण है कि हम देखना चाहेंगे कि परिवर्तनके लिए किसने अनुमति दी है। इस पीठमें न्यायमूर्ति जायमाल्या बागची और न्यायमूर्ति बी. मोहना भी शामिल हैं। सर्वोच्च न्यायालयके अधिवक्ता शैलेन्द्रमणि त्रिपाठीकी ओरसे दाखिल याचिकापर सुनवाई करते हुए पीठने जो व्यवस्था और टिप्पणी दी है उसके व्यापक सन्दर्भोंमें भी देखना उचित होगा। याचिकामें यह भी मांग की गयी थी मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्यके खिलाफ काररवाई की जानी चाहिए, क्योंकि इसमें दो अन्य आयुक्तों एस.एस. सन्धू और विवेक जोशीकी आपत्तियोंको दरकिनार कर फार्म-६ में परिवर्तन किया गया था। इस प्रकरणको राजनीतिक मुद्दा बनाकर विरोध भी किया गया। इसे विवादके रूपमें देखना पूरी तरहसे उचित नहीं माना जा सकता, क्योंकि इसका महत्व उससे भी कहीं अधिक बड़ा है। यह मामला मतदाता पंजीकरण, चुनाव आयोगकी संवैधानिक शक्तियों, संस्थागत निर्णय-प्रक्रिया और मताधिकारकी सुरक्षासे जुड़ा है। पीठने चुनाव आयोगसे मूल रिकार्ड मंगाकर यह देखनेकी बात कही है कि वास्तवमें क्या परिवर्तन हुआ और उसे किसने अधिकृत किया। यह स्पष्टीकरण इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि २६ सितम्बरको चुनाव आयोगकी ओरसे जारी विज्ञप्तिमें कहा गया था कि एसआईआरके लिए फार्म-६ से जुड़ी घोषणाको सर्वोच्च न्यायालयने बरकरार रखा है। इसे चुनाव आयोगकी शक्तियोंपर रोकके रूपमें नहीं, बल्कि शक्तियोंकी सीमाके परीक्षणके रूपमें देखना चाहिए। यह भी जरूरी है कि यदि किसी नियमके तहत फार्म-६ के मूल स्वरूपमें परिवर्तन किया गया है तो उसमें निर्धारित वैधानिक प्रक्रियाका पालन हुआ है कि नहीं। सबसे गम्भीर पहलू यह है कि क्या प्रशासनिक सुविधासे वैधानिक प्रक्रिया बदली जा सकती है? मतदाताके अधिकारके दृष्टिकोणसे यह मामला अत्यन्त महत्वपूर्ण माना जायगा। इस पूरे विवादका दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष स्वयं निर्वाचन आयोगकी आन्तरिक निर्णय प्रक्रियासे सम्बन्धित है। इसे राजनीतिक आरोपोंसे अलग रखकर देखना ज्यादा उचित होगा। सर्वोच्च न्यायालयकी टिप्पणी चुनाव आयोगके अधिकारोंको कमजोर करने नहीं, बल्कि संवैधानिक अधिकारोंके प्रयोगकी सीमा निर्धारित करने वाली टिप्पणी है। इस मामलेका वास्तविक महत्व अदालतके अन्तिम निर्णयपर आधारित है।

घुसपैठियोंका निर्वासन

यह भारतके लिए गम्भीर चिन्ताका विषय और खतरेका संकेत है कि वे बड़ी संख्यामें बंगलादेशी घुसपैठिये देशके विभिन्न राज्योंमें पैर जमा चुके हैं और लम्बे समयसे अवैध रूपसे रह भी रहे हैं। यहां यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि क्या देशकी सीमाएं इतनी असुरक्षित हैं कि भारतके प्रति विद्वेषकी भावना रखने वाले देशोंके नागरिकोंको देशमें प्रवेशको प्रोत्साहित करते हैं। भारतने इन घुसपैठियोंके प्रति कड़ा रुख अपनाया है, जिन्हें चिह्नित कर पकड़ा जा रहा है और अब इनके विरुद्ध काररवाई निर्वासनतक पहुंच गयी है, जो उचित और समयानुकूल है। जम्मू-कश्मीरमें ऐसे घुसपैठियोंके खिलाफ कड़ी काररवाई करते हुए प्रशासनने सोमवारको १५० बंगलादेशियोंको विशेष भारतीय वायुसेनाके विमानसे श्रीनगरसे पश्चिम बंगालके बागडोगरा भेज दिया और उन्हें सीमा सुरक्षा बलके हवाले कर दिया। पुलिस अधिकारियोंके अनुसार अभी १५० और बंगलादेशी नागरिकोंको गुरुवारको डिपोर्ट किया जायगा। यानी दो चरणोंमें जम्मू-कश्मीरमें अवैध रूपसे रह रहे कुल तीन सौ लोगोंके निर्वासनकी तैयारी है। जम्मू-कश्मीरमें जनसांख्यिकी बदलावका आकलन करनेके लिए इसी वर्ष अगस्तमें केन्द्र सरकारके एक उच्चस्तरीय दलने दौरा किया था। एक अनुमानके अनुसार लगभग १५००० बंगलादेशी और रोहिंग्या प्रदेशमें रह रहे हैं, जो नागरिक सुरक्षाके लिए भी बड़ी चुनौती है। बड़ी बात है कि न तो इनके पास कोई वैध दस्तावेज है, न ही प्रशासनके पास इनका कोई रिकार्ड ही है। इसके बावजूद इनके पाससे फर्जी आधार कार्ड एवं राशन कार्ड बरामद होना हैरान करने वाला है। इतनी बड़ी संख्यामें किसी एक राज्यमें रह रहे घुसपैठिये इस बातका सुबूत है कि कोई बड़ा नेटवर्क इनके बसाने और सभी सुविधा उपलब्ध करानेमें सक्रिय है। इनके विरुद्ध काररवाई करनेकी जरूरत है। इस नेटवर्कमें राजनीतिक दलकी संलिप्तासे इनकार नहीं किया जा सकता है। घुसपैठियोंके डिपोर्टसे ही समस्याका समाधान नहीं होगा। देशके दुश्मन जयचन्दोंके विरुद्ध कड़ी काररवाई होनी चाहिए, जो लोगोंके लिए सबक बने।

लोक संवाद

मच्छारसे अपनत्व

महोदय,- इन दिनों भारतीय मूलके कैप्टन स्मित मच्छार सुर्खियोंमें हैं। वे संयुक्त अरब अमीरातकी सरकारी विमानन सेवा फ्लाई दुबईमें पाइलट थे। हालमें तेल अवीव जाती हुई एक उड़ानमें उनके सह पाइलटने उनपर चाकूसे हमला किया, जिस दौरान वे काकपिटका दरवाजा खोलनेमें सफल रहे, जिससे अन्य यात्रियों, जिनमें दो पाइलट भी थे, की मददसे जहाज सही उतार लिया गया। भारतीय इसपर गर्व कर रहे हैं। हालांकि वे यह भूल जाते हैं कि सन् २०२२ में बेहतर जाबके लिये स्मितको यह विदेशी विमानन कम्पनी चुननी पड़ी और वे सपरिवार दुबईमें ही रहने लगे। स्वदेश उन्हें अच्छा कैरियर नहीं दे सका और प्रतिभा पलायन हुआ। ऐसे ही कभी महान् वैज्ञानिक डा. हरगोविंद खुराना भी अमेरिका वासी बने और वहां एक बड़ा आविष्कार करके विश्व प्रसिद्ध हुए थे। **-रघोत्तम शुक्ल, वाया ईमेल।**

जरूरी मुद्दोंका अभाव विपक्षकी अक्षमता

भारतीय लोकतंत्रकी खूबसूरती यह है कि यहां कोई भी सरकार स्थायी नहीं होती और कोई भी विपक्ष हमेशाके लिए नहीं रहता। मतदाता सरकारसे उसके कामकाजपर सवाल उठा सकता है, फिर भी केवल नाराजगीके आधारपर किसी ऐसे विकल्पको स्वीकार नहीं करता, जिसके पास देशके भविष्यकी स्पष्ट रूपरेखा न हो।

❐ ललित गर्ग

भारतीय राजनीतिमें विपक्षके सामने मूल प्रश्न यही है-क्या वह केवल सरकारसे असंतुष्ट है या जनताके सामने कोई विश्वसनीय विकल्प भी रख रहा है। राहुल गांधी लम्बे समयसे यह सवाल उठा रहे हैं कि मोदी सरकारके प्रति अपेक्षित एंटी-इंकंबेंसी दिखाई क्यों नहीं देती। उनका आरोप है कि चुनावी प्रक्रियामें गड़बड़ी और वोट चोरीके कारण जनताकी वास्तविक इच्छा सामने नहीं आ पा रही। इन आरोपोंके समर्थनमें उनके द्वारा प्रस्तुत दावोंको लेकर राजनीतिक और कानूनी बहस जारी है, उन्हें अंतिम रूपसे सिद्ध तथ्य मानना अभी उचित नहीं होगा। लेकिन इतना जरूर है कि चुनावी प्रक्रिया, मतदाता सूची और निर्वाचन आयोगकी पारदर्शितापर उठने वाले प्रत्येक प्रश्नका निष्पक्ष और तथ्यात्मक उत्तर मिलना लोकतंत्रके हितमें है। इसी संदर्भमें एसआईआर यानी मतदाता सूचीके विशेष गहन पुनरीक्षणका विवाद महत्वपूर्ण हो गया है। निर्वाचन आयोग स्वयं एसआईआर २०२६ से संबंधित मतदाता सेवाएं और मतदाता सूची उपलब्ध करा रहा है तथा वह अपनेको स्वतंत्र संवैधानिक प्राधिकरण बताता है। दूसरी ओर विपक्षने इस प्रक्रिया और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमारकी कार्यप्रणालीपर गम्भीर सवाल उठाये हैं। इस विवादको अब सर्वोच्च न्यायालयमें भी चुनौती मिली है। इस पूरे मामलेका अंतिम निष्कर्ष राजनीतिक नारोंसे नहीं, संवैधानिक और न्यायिक प्रक्रियासे निकलेगा। यहीं विपक्षकी राजनीतिकी असली परीक्षा शुरू होती है। चुनाव आयोगके विरुद्ध आन्दोलन करना विपक्षका लोकतांत्रिक अधिकार है। मतदाता सूचीमें यदि किसी पात्र नागरिकका नाम गलत ढंगसे हटाया गया है तो उसका विरोध होना चाहिए। यदि किसी अधिकारीने नियमोंका उल्लंघन किया है तो उसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन लोकतंत्रकी रक्षा केवल आयोगके विरोधसे नहीं होगी। लोकतंत्रकी रक्षा तब होगी जब विपक्ष जनताको यह भी बताये कि सत्ता मिलनेपर वह शिक्षा, रोजगार, कृषि, उद्योग, स्वास्थ्य, शहरी जीवन, कानून-व्यवस्था और प्रशासनमें क्या बदलेगा।



लोकतंत्रमें सरकारकी जवाबदेही जितनी जरूरी है, विपक्षकी जवाबदेही भी उतनी ही जरूरी है। सत्तासे मोहभंग लोकतंत्रका स्वाभाविक हिस्सा है, लेकिन उस मोहभंगको राजनीतिक परिवर्तनमें बदलनेके लिए विश्वसनीय विकल्प चाहिए। आज इण्डी गठबंधनके सामने चुनौती भाजपा और नरेन्द्र मोदीसे लड़नेसे बड़ी है। उसे जनताके मनमें यह विश्वास पैदा करना है कि उसके पास भारतके अगले दशककी कोई स्पष्ट, ठोस और क्रियान्वित करने योग्य कहानी भी है। विपक्ष यदि यह विश्वास पैदा कर पाया तो चुनाव आयोगका मुद्दा भी लोकतांत्रिक सुधारकी सार्थक बहस बनेगा।

यही वह बिन्दु है जहां वोट चोरीका राजनीतिक विमर्श जनताके रोजमर्राके सवालोंसे टकराता है। एक सामान्य परिवारको बच्चोंकी महंगी शिक्षाकी चिन्ता है। रोजगारकी बदलती प्रकृति, एआई और नयी तकनीकके कारण पारम्परिक कौशल तेजीसे अप्रासंगिक हो रहे हैं। डिग्री लेनेके बाद भी रोजगारकी गारंटी नहीं है। प्रतियोगी परीक्षाओंमें पेपर लीक और नकलकी घटनाएं युवाओंके विश्वासको चोट पहुंचाती हैं। ऐसेमें युवा यह जानना चाहता है कि अगली सरकार परीक्षा व्यवस्थाको कैसे विश्वसनीय बनायेगी, स्कूलोंकी गुणवत्ता कैसे सुधारेगी और बदलती तकनीकी अर्थव्यवस्थाके लिए करोड़ों युवाओंको तैयार कैसे करेगी। किसानकी समस्या भी केवल एमएसपी या आन्दोलनतक सीमित नहीं है। फसल आनेपर कीमत गिर जाती है और कुछ महीने बाद वही प्याज, टमाटर या दूसरी सब्जियां महंगी हो जाती हैं। इसका समाधान केवल विरोधमें नहीं, बल्कि गांव-कस्बेतक भंडारण, कोल्ड-चेन, प्रसंस्करण, कृषि बाजार और मूल्यवर्धनकी मजबूत व्यवस्थामें है। विपक्ष यदि कृषि सुधारोंका विरोध करता है तो उसे यह भी बताना होगा कि वह वैकल्पिक कृषि ढांचा किस तरह खड़ा करेगा।

रोजगारका प्रश्न इससे भी बड़ा है। भारतकी युवा आबादीको उद्योग, विनिर्माण, सेवा क्षेत्र, अनुसंधान और नयी तकनीकसे जोड़ना होगा। निवेशके लिए स्थिर कानून-व्यवस्था, पारदर्शी प्रशासन और भरोसेमंद कारोबारी वातावरण जरूरी है। केवल बड़े उद्योगपतियोंपर राजनीतिक प्रहार या संपत्तिकी गणना जैसे नारोंसे रोजगार पैदा नहीं होते। विपक्ष यदि संपत्तिके पुनर्वितरण या सामाजिक न्यायकी बात करता है तो उसे साथ ही यह भी बताना होगा कि संपत्ति और अवसर कैसे पैदा किये जायंगे। जितनी आबादी, उतना हक जैसी राजनीति सामाजिक प्रतिनिधित्वके प्रश्नको सामने लाती है, लेकिन आजकी चुनौती प्रतिनिधित्वके साथ-साथ क्षमता निर्माणकी भी है। पिछड़े, दलित, आदिवासी और कमजोर वर्गोंके बच्चोंको अच्छी शिक्षा, कौशल, स्वास्थ्य और अवसर मिलें-यह सामाजिक न्यायका अधिक स्थायी आधार है। केवल आंकड़े गिनना पर्याप्त नहीं, उन आंकड़ोंके पीछे खड़े मनुष्यका जीवन बदलना जरूरी है। इस पूरे परिदृश्यमें ममता बनर्जीकी भूमिका विशेष चर्चाका विषय बनी है। राष्ट्रीय विपक्षी राजनीतिमें उनकी भूमिकाको लेकर नया विमर्श अवश्य उभरा है। हालकी इंडिया गठबंधनकी बैठकमें उन्होंने विपक्षका दायरा बढ़ाने और व्यापक एकताकी आवश्यकतापर जोर दिया। यह बदलाव इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इंडिया गठबंधनका सबसे बड़ा संकट केवल भाजपासे मुकाबला नहीं, बल्कि उसके भीतरका परस्पर अविश्वास है। सीटोंका बंटवारा, क्षेत्रीय वर्चस्व, नेतृत्वका प्रश्न और राज्योंमें एक-दूसरेके खिलाफ लड़ने वाली पार्टियोंका राष्ट्रीय स्तरपर साथ आना आसान नहीं है। आजकी स्थितिमें आपका चुनाव आयोगतक प्रस्तावित मार्चसे अलग रहकर अपना रास्ता अपनाना भी इस अंतर्विरोधको दिखाता है।

कांग्रेस, तृणमूल, समाजवादी पार्टी, वामपंथी दल, राजद, आप और दूसरे क्षेत्रीय दल जब अलग-अलग राज्योंमें अलग-अलग राजनीति करते हैं, तब राष्ट्रीय मंचपर उनका साझा न्यूनतम कार्यक्रम क्या है। जनता इसीका उत्तर चाहती है। चुनाव आयोगके मुद्देपर भी यही कसौटी लागू होती है। इंडिया गठबंधनने ६ अक्तूबरको निर्वाचन आयोगतक मार्च सहित विरोध कार्यक्रम घोषित किये हैं और ज्ञानेश कुमारके इस्तीफेकी मांग उठायी है। यह आन्दोलन संवैधानिक प्रश्नोंको सार्वजनिक बहसके केन्द्रमें ला सकता है। लेकिन यदि विपक्षका पूरा राजनीतिक अभियान केवल एक व्यक्तिके इस्तीफेतक सीमित रह गया तो इससे चुनावी संस्थाओंपर व्यापक विश्वासका प्रश्न हल नहीं होगा। उसे यह भी बताना होगा कि सत्तामें आनेपर निर्वाचन आयोगकी नियुक्ति, मतदाता सूची, ईवीएम-वीवीपैट, चुनावी चंदे और चुनावी पारदर्शिताको लेकर वह कौनसे संस्थागत सुधार करेगा।

बड़ा प्रश्न है कि सत्ताकी पात्रताको विकसित करनेके लिए विपक्ष क्यों नहीं जनतासे जुड़े मुद्दोंको लेकर सकारात्मक राजनीतिको बल देती। वास्तवमें विपक्षके सामने सबसे बड़ा संकट मुद्दोंकी कमी नहीं, मुद्दोंको समाधानमें बदलनेकी क्षमताका है। बेरोजगारी है, शिक्षाका संकट है, कृषिकी समस्या है, स्वास्थ्यका खर्च है, महंगीकी चिन्ता है, शहरी प्रदूषण है, एआईसे बदलती नौकरियां हैं और वैश्विक अर्थव्यवस्थामें भारतकी प्रतिस्पर्धाका प्रश्न है। जनता इन सबको प्रतिदिन महसूस करती है। लेकिन राजनीतिक विमर्श बार-बार मोदी बनाम कौन, राहुल बनाम मोदी, ईवीएम बनाम बैलेट और आयोग बनाम विपक्षकी बहसमें सिमट जाता है। भारतीय मतदाता सरकारसे मोहभंग होनेपर भी यह देखता है कि उसके सामने विकल्प क्या है। वह जमीन छोड़कर अंधे कुएंमें छलांग नहीं लगाता। उसे ऐसा विपक्ष चाहिए जो सरकारकी कमियां गिनानेके साथ अपनी क्षमताएं भी बताये, जो केवल सत्ताकी आलोचना नहीं, शासनका वैकल्पिक मॉडल प्रस्तुत करे, जो चुनाव आयोगसे सवाल पूछे तो अपनी चुनावी पारदर्शिताकी कसौटी भी सामने रखे, जो सामाजिक न्यायकी बात करे तो शिक्षा और अवसरका रास्ता भी बताये, जो उद्योगपतियोंसे सवाल करे तो निवेश और रोजगारकी अपनी नीति भी स्पष्ट करे। लोकतंत्रमें सरकारकी जवाबदेही जितनी जरूरी है, विपक्षकी जवाबदेही भी उतनी ही जरूरी है। सत्तासे मोहभंग लोकतंत्रका स्वाभाविक हिस्सा है, लेकिन उस मोहभंगको राजनीतिक परिवर्तनमें बदलनेके लिए विश्वसनीय विकल्प चाहिए। आज इंडिया गठबंधनके सामने चुनौती भाजपा और नरेन्द्र मोदीसे लड़नेसे बड़ी है। उसे जनताके मनमें यह विश्वास पैदा करना है कि उसके पास भारतके अगले दशककी कोई स्पष्ट, ठोस और क्रियान्वित करने योग्य कहानी भी है। विपक्ष यदि यह विश्वास पैदा कर पाया तो चुनाव आयोगका मुद्दा भी लोकतांत्रिक सुधारकी सार्थक बहस बनेगा, ममता बनर्जीकी भूमिका भी सार्थक होगी और राहुल गांधीके सवाल भी व्यापक राजनीतिक विमर्शका हिस्सा बनेंगे।

भारतकी परिपक्व कूटनीतिका प्रमाण

रूस और यूक्रेनके बीच चल रहे लम्बे संघर्षने पूरी दुनियाको एक अभूतपूर्व संकटमें डाल दिया है। इस युद्धकी शुरुआतमें भारतने एक तटस्थ दृष्टिकोण अपनाया था और सभी पक्षोंसे बातचीतके माध्यमसे शांति स्थापित करनेकी अपील की थी।

❐ महेन्द्र तिवारी

वर्तमान वैश्विक परिदृश्यमें कूटनीतिके मायने तेजीसे बदल रहे हैं। रूस और यूक्रेनके बीच युद्ध खिंचता गया भारतकी कूटनीतिक रणनीतिमें एक बड़ा और सकारात्मक बदलाव देखनेको मिला है। आज भारत केवल युद्धविरामकी औपचारिक अपीलतक सीमित नहीं है, बल्कि वह इस संघर्षसे उपजी ठोस और व्यावहारिक समस्याओंके समाधानके लिए एक सक्रिय मध्यस्थकी भूमिका निभा रहा है। यह बदलाव विश्वपटलपर भारतकी उस छविको मजबूत कर रहा है जो उसे एक जिम्मेदार और प्रभावी वैश्विक शांति निर्माताके रूपमें स्थापित करती है। वर्ष १९४७ में अपनी स्वतंत्रताके बादसे ही भारतने अंतरराष्ट्रीय विवादोंसे खुदको दूर रखनेकी नीतिका पालन किया था, ताकि वह अपने आंतरिक विकासपर ध्यान दे सके। लेकिन २१वीं सदीका भारत एक अत्यंत शक्तिशाली और आत्मविश्वाससे भरा राष्ट्र है। आजकी बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्थामें कोई भी बड़ी घटना भारतको अछूता नहीं छोड़ सकती है। इसलिए भारतने अपनी पुरानी संकोचशील नीतिको त्याग कर एक सक्रिय और मुखर विदेश नीति अपनायी है। रूस और यूक्रेनके संदर्भमें यह मुखरता स्पष्ट रूपसे दिखाई देती है। विश्व अब यह मान चुका है कि भारत केवल मूकदर्शक बनकर नहीं बैठ सकता है। भारतने अपना ध्यान उन मुद्दोंपर केन्द्रित किया है जिनका सीधा असर पूरी मानवता और विशेषकर गरीब देशोंपर पड़ रहा है। इस युद्धने दुनियाभरमें खाद्यान्न संकट और ऊर्जाकी कमीको जन्म दिया है। ऐसेमें भारतने अपनी कूटनीतिक ऊर्जाको उन क्षेत्रोंमें लगाया है जो वैश्विक अर्थव्यवस्थाको पतनसे बचा सकते हैं। इस दिशामें सबसे महत्वपूर्ण कदम काला सागरमें व्यापारिक जहाजोंकी सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करनेका प्रयास है। युद्धके कारण इस मार्गसे होने वाला व्यापार बुरी तरह बाधित हुआ है जिससे कई देशोंमें भुखमरी और महंगीका संकट खड़ा हो गया। भारतने रूस और यूक्रेन दोनोंके साथ अपनी बातचीतमें इस बात पर विशेष जोर दिया है कि खाद्यान्न और उर्वरक ले जाने वाले जहाजोंको युद्धका निशाना न बनाया जाय। भारतने संयुक्त राष्ट्रके साथ मिलकर इस बातपर जोर दिया है कि अनाजकी आपूर्तिको राजनीति या युद्धका हथियार नहीं बनाया जा सकता है। जहाजोंको सुरक्षित निकालनेके लिए बनाये गये समुद्री मार्गोंके समर्थनमें भारतकी आवाजने एक बड़ा कूटनीतिक दबाव बनाया है।

खाद्य सुरक्षाके साथ ही ऊर्जा कूटनीति इस संघर्षका एक अन्य अत्यंत संवेदनशील पहलू है। युद्ध क्षेत्रोंमें स्थित परमाणु ऊर्जा संयंत्रोंकी सुरक्षाको लेकर पूरी दुनियामें गहरी चिन्ता व्याप्त है। किसी भी दुर्घटनाकी स्थितिमें इसका परिणाम आने वाली कई पीढ़ियोंको भुगतना पड़ सकता है। भारतने अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा नियमोंका हवाला देते हुए दोनों देशोंके नेतृत्वको इन संयंत्रोंकी सुरक्षा सुनिश्चित करनेके लिए राजी करनेका निरन्तर प्रयास किया है। इसके अतिरिक्त ऊर्जा संसाधनोंके निर्बाध प्रवाहको बनाये रखनेके लिए भी भारतकी बातचीत बेहद महत्वपूर्ण रही है। यह सुनिश्चित करना कि युद्धके कारण दुनियाके अन्य देश अंधकार या भीषण सर्दीका शिकार न हों यह भारतकी परिपक्व कूटनीतिका बेहतरीन प्रमाण है।

भारतकी इस सक्रिय भूमिकाका एक बड़ा कारण विकासशील और गरीब देशोंके हितोंकी रक्षा करना भी है। इस युद्धका सबसे विनाशकारी आर्थिक परिणाम पश्चिमी देशोंने नहीं, बल्कि एशिया, अफ्रीका और लातिन अमेरिकाके उन देशोंने उठाया है जो पहलेसे ही बड़ी आर्थिक चुनौतियोंसे जूझ रहे थे। भारतने अंतरराष्ट्रीय मंचोंपर मजबूतीसे यह बात रखी है कि यूरोपकी समस्याको पूरी दुनियाकी समस्या नहीं माना जाना चाहिए लेकिन इस युद्धके आर्थिक परिणामोंसे कोई भी देश अछूता नहीं रह सकता है। जब भारत काला सागरकी सुरक्षा या उर्वरकोंकी आपूर्तिकी बात करता है तो वह केवल अपने लिए नहीं, बल्कि उन तमाम देशोंके लिए बोल रहा होता है जिनकी आवाज वैश्विक मंचोंपर अक्सर अनसुनी कर दी जाती है। हालके महीनोंमें भारतीय नेतृत्व द्वारा किये गये उच्चस्तरीय संवाद इस बातका जीवंत प्रमाण हैं कि भारत शांतिकी प्रक्रियामें कितना गहराईसे निवेश कर रहा है। भारतने अपनी कूटनीतिक कुशलता से इस दरवाजेको बंद नहीं होने दिया है। यह इस बातको भी दर्शाता है कि भारतकी विदेश नीति कितनी स्वतंत्र और लचीली है।

भारतकी इस मध्यस्थताकी सफलताका सबसे बड़ा कारण उसका दोनों पक्षोंके बीच समान रूपसे विश्वसनीय होना है। वर्तमानमें बहुत कम देश ऐसे हैं जो रूस और यूक्रेन दोनोंके साथ बिना किसी पूर्वाग्रहके बातचीत कर सकते हैं। रूसके साथ भारतके ऐतिहासिक और रणनीतिक संबंध बहुत गहरे हैं इसलिए रूसी नेतृत्व भारतकी चिन्ताओंको बहुत गम्भीरतासे लेता है। दूसरी ओर भारतने क्षेत्रीय अखंडता और देशोंकी संप्रभुताके सम्मानपर निरन्तर जोर देकर यूक्रेन तथा अन्य पश्चिमी देशोंका भी पूरा विश्वास हासिल किया है। भारतकी यह निष्पक्षता उसे अन्य देशोंके उन प्रयासोंसे अलग करती है, जिन्हें अक्सर संदेहकी दृष्टिसे देखा जाता है। भारतकी यह यात्रा उसकी विदेश नीतिके एक नये युगका प्रतीक है। इसका अर्थ यह नहीं है कि भारत किसी सैन्य गुटका हिस्सा बन रहा है, बल्कि इसका अर्थ यह है कि भारत हर उस देशके साथ खड़ा है जो शांति, विकास और मानवताके पक्षमें है। भारतीय संस्कृतिका मूल विचार जो पूरी पृथ्वीको एक परिवार मानता है उसने इस कूटनीतिको एक गहरा दार्शनिक आधार प्रदान किया है। अंतत: यह स्पष्ट रूपसे कहा जा सकता है कि रूस और यूक्रेनके बीच चल रहे इस टकरावमें भारतकी भूमिका एक मूकदर्शक या केवल उपदेश देने वाले देशकी बिल्कुल नहीं रह गयी है। ठोस आर्थिक और मानवीय मुद्दोंपर बातचीत करके, सुरक्षित व्यापारिक मार्ग सुनिश्चित करवाकर और परमाणु सुरक्षा जैसे अत्यंत गम्भीर विषयोंपर हस्तक्षेप करके भारतने विश्वको यह दिखा दिया है कि वह सबसे जटिल भू-राजनीतिक समस्याओंका भी व्यावहारिक समाधान देनेकी असीम क्षमता रखता है। यही वह अद्वितीय कूटनीतिक कौशल है जो आने वाले समयमें वैश्विक व्यवस्थामें भारतके कदको और अधिक ऊंचा करेगा और उसे सही मायनोंमें विश्वमें शांति स्थापित करने वाले एक प्रमुख और जिम्मेदार राष्ट्रके रूपमें हमेशाके लिए मान्यता दिलायेगा।



निष्काम भाव

❐ बाबा हरदेव

जन्म लेना प्राकृतिक घटना है। यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्व इस बातका है कि जन्मके बाद निष्काम कर्म अथवा अकर्म करनेपर सही अर्थोंमें जीवन मिल सकता है। जन्म तो केवल महान जीवनकी संभावना मात्र है। ऋषियोंका कथन है कि मनुष्यकी आयुसे वास्तविक जीवन और निष्काम जीवनका पता नहीं चलता। मनुष्य कैसा जीवन जीता है, कैसे निष्काम कर्म करता है, इससे इसके असली जीवन जीनेका पता चलता है। अत: जीवनका संबंध लंबी आयुसे कम है, बल्कि जीवनका महत्व तो ज्यादा निष्काम कर्मसे जुड़ा है, क्योंकि जीवनका अस्तित्व संज्ञाओंसे नहीं बनता, बल्कि जीवन क्रियाओंसे निर्मित होता है। अब वास्तविकता यह है कि शुभ और निष्काम कर्मका भाव तो मनुष्य जीवनमें परमात्माकी प्राप्तिके बाद ही शुरू होता है। जब मनुष्य पूर्ण सतगुरु द्वारा धार्मिकताकी सतत धाराको अनुभव करता है फिर मनुष्यका जीवन सुगंधसे भर जाता है ऐसी सुगंध जो फिर कभी नहीं चूकती। ऐसी सुगंधको अध्यात्ममें निष्काम कर्मके नामसे संबोधित किया जाता है। धर्म निष्काम कर्म है, लेकिन निष्काम कर्म, धर्म नहीं है। इनमें बड़ा अंतर है। यदि निष्काम कर्म धर्म है तो फिर निष्काम कर्म धर्मसे ऊपर हो गया, परंतु ऐसा नहीं है। इसलिए मनुष्यको पहले धर्मिकताके वास्तविक रहस्यको पूर्ण सतगुरुसे समझना होगा फिर मनुष्य निष्काम कर्म करनेवाला हो जायगा। निष्काम कर्म फिर छायाकी तरह मनुष्यके साथ-साथ चलेगा अर्थात् मनुष्य ऐसे निष्काम कर्ममें समा जायगा। स्पष्ट है कि मनुष्य फिर निष्काम कर्म करके इसके पीछे भी नहीं खड़ा होगा और न ही निष्काम कर्म, परोपकारका उपयोग करनेके बाद इसे पीछे खड़ा होकर देखेगा। अपितु इस अवस्थामें निष्काम कर्मका उपयोग करके मनुष्य स्वयं पीछे हट जायगा तथा मनुष्यके मनमें फिर अकर्तापनका भाव आ जायगा। इस प्रकारके निष्काम भावसे किये गये कर्मको शब्द भी पूरी तरह नहीं कह पाते। ऐसा निष्काम कर्म तो मनुष्यके लिए एक आनन्दका कारण होता है, उत्सवके समान होता है। अंतमें यही कहना ठीक होगा कि जो व्यक्ति ईश्वरके प्रति समर्पित और निष्काम भावसे किये गये कर्मको करता हुआ जीवन व्यतीत करता है, उसके लिए वही जीवन ईश्वरकी उपासना बन जाता है। इसका प्रत्येक कर्म एक प्रार्थनाके समान होता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोणसे निष्काम कर्म मनुष्यके लिए सबसे बड़ी संपदा है, क्योंकि निष्काम भावसे कर्म करनेवाला कर्मयोगी मनुष्य कभी भी अधूरा नहीं होता है।

किसानको कब मिलेगा सफेद सोनेका वाजिब दाम

❐ डा. जितेन्द्र सिंह

उथले पानीमें उगने वाली मखानाकी फसल किसानोंके लिए अब गहरी कमाईका जरिया बन रही है। इसे अब राष्ट्रीय मखाना बोर्ड, सरकारी सब्सिडी और वैश्विक बाजारका सहारा भी मिल रहा है। मखाना तालाबके ठहरे पानीकी सतहपर बड़े गोल पत्ते और उसके नीचे कीचड़में काले, गोल बीज, जिन्हें स्थानीय लोग गुर्री कहते हैं। यही काले बीज प्रसंस्कृत होकर जब बाजार पहुंचते हैं तो लोग उन्हें मखाना और कारोबारी सफेद सोना कहते हैं। कभी व्रत-उपवासतक सीमित रहा मखाना, अब शहरोंकी रसोईमें सुपरफूडके रूपमें जगह बना चुका है। इसके पीछे किसानकी मेहनत हैं। मखाना सिंघाड़ेकी तरह जलकी सतहपर तैरने वाली फसल है। इसके बीजोंको प्रसंस्कृत कर सूखे फल (लावा) के रूपमें बेचा जाता है। यह पौष्टिक तत्वोंसे भरपूर है। किसानों और ग्रामीणोंके लिए अच्छी आय देने वाली नकदी फसल भी है। फलाहारमें इसकी खपत बड़े पैमानेपर होती है। इसे सब्जीके रूपमें, घीमें भूनकर, हलवा बनाकर, नमकीन और स्नैक्समें भी खूब इस्तेमाल किया जाता है। देशमें मखाना उत्पादनका बड़ा हिस्सा बिहारसे आता है। राज्य कृषि विभागके आंकड़ोंके मुताबिक देशके कुल उत्पादनमें बिहारकी हिस्सेदारी लगभग ८५ प्रतिशत है। कई स्रोत तो इसे ९० फीसदीतक बताते हैं। मखाना उत्पादन मुख्य रूपसे मिथिलांचलके नौ जिलोंमें केन्द्रित है। मधुबनी, दरभंगा, पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, अररिया, सीतामढ़ी और किशनगंजमें इसकी बड़े पैमानेपर खेती होती है। सर्वाधिक उत्पादन इसका सहरसामें होता है। रकबे और उत्पादनके आंकड़ेपर जाय तो बिहारमें लगभग ३५ हजार हेक्टेयर क्षेत्रसे लगभग दस हजार टन वार्षिक उत्पादन होता है। इस तरहसे बिहारके मखाना उद्योगका कारोबार लगभग तीन हजार करोड़ रुपयेका है। पहचानके मोर्चेपर बड़ी उपलब्धि २०२२ में मिली, जब मिथिला मखानाको भौगोलिक संकेतक (जीआई) का दर्जा दिया गया। यहांसे मखाना अमेरिका, आस्ट्रेलिया, फ्रांस, जापान और इंग्लैंड जैसे देशोंको भेजा जाता है।

मखाना क्षेत्रके लिए सबसे बड़ा नीतिगत मोड़ केन्द्रीय बजट २०२५-२६ में आया। वित्तमंत्रीने बिहारमें मखाना बोर्ड बनानेकी घोषणा की, जिसका मकसद उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और विपणनको बढ़ावा देना था। इसके बाद प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदीने १५ सितंबर २०२५ को पूर्णियामें राष्ट्रीय मखाना बोर्डका उद्घाटन भी किया। सरकारका यह कदम आने वाले दिनोंमें इस व्यवसायके लिए मीलका पत्थर साबित होगा। मखाना बोर्डके पीछे बड़ा वित्तीय आधार है। केन्द्रकी छह वर्षीय (२०२५-२६ से २०३०-३१) योजना ४७६ करोड़ रुपयेकी है। बोर्डके काममें किसानोंको प्रशिक्षण, बाजारतक पहुंच, निर्यातको बढ़ावा और आईसीएआर, नाबार्ड एवं कृषि विश्वविद्यालयोंके साथ साझ